योजनाओं का विकेंद्रीकरण आवश्यक

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा पर बोलते सुदेश महतो। • हिन्दुस्तान

डिप्टी सीएम सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि विकास के लिए योजनाओं का विकेन्द्रीकरण होना जरूरी है। इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार योजनाओं का चयन ग्राम स्तर पर कराने का प्रयास कर रही है। केन्द्र की कई ऐसी योजनाएं है, जिसमें क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया है। योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में भौगोलिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डिप्टी सीएम सोमवार को होटल बीएनआर चाणक्य में विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा पर आयोजित दो दिवसीय मीडिया कार्यशाला में बोल रहे थे। यह कार्यशाला सीएसडीएस, दिल्ली की शाखा आइएम फॉर चेंज और योजना आयोग के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित है। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश ने कहा कि जनप्रतिनिधि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होने देना चाहते हैं। योजना एवं विकास सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि योजना की सफलता में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आइएम फॉर चेंज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. विपुल मुदगल ने विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण बहुत आसान है। सीडीडीपी के विशेषज्ञ सुंदर एन मिश्रा ने केन्द्रीय योजनाओं का उल्लेख किया।

यूएनडीपी के गवर्नेंस एडवाइजर टीआर रघुनंदन ने कहा कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत को अधिकार सौंपने की जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी गई है। झारखंड का पंचायत कानून काफी सख्त है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। राज्यों में केन्द्रीय योजनाओं को जैसे-तैसे क्रियान्वित किया जा रहा है। झारखंड का योजना बजट योजना आयोग से जून में पास होगा, जबकि इसे मार्च में पास हो जाना चाहिए था। कार्यशाला में प्रो. रमेश शरण और सुधीर पाल ने योजनाओं के कार्यान्वन में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला।

प्रो. शरण ने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जनप्रतिनिधियों को अपना नजरिया बदलनी होगी। ग्राम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिए।